

आरक्षण नीति

RESERVATION - POLICY

(xxxiv) अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण नीति

सेवाओं में आरक्षण

हरियाणा राज्य में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये सभी सरकारी विभागों/बोर्डों/निगमों/सहकारी संस्थाओं/वि विद्यालयों तथा स्वायत्तसासी संस्थाओं आदि की सेवाओं में आरक्षण का वर्तमान कोटा निम्न प्रकार से है:-

(क) सीधी भर्ती

1. अनुसूचित जाति 20% श्रेणी I, II, III तथा IV में (10% ब्लाक 'ए' तथा 10% ब्लाक 'बी')
2. पिछड़े वर्ग 10% श्रेणी I तथा II में (कोई ब्लाक नहीं है) 27% श्रेणी III तथा IV में (16% ब्लाक 'ए' तथा 11% ब्लाक 'बी')

(ख) पदोन्नति

अनुसूचित जाति 20% श्रेणी III तथा IV में

सेवाओं में आरक्षण सम्बन्धी मुख्य हिदायतों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:-

- सरकार की हिदायतें क्रमांक 22/93/2002-3जी0एस0 III दिनांक 03-03-2002 के अनुसार जहां दो या दो से अधिक पद स्वीकृत हों वहां पर आरक्षण लागू है । मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 22/63/2000-3जी0एस0 III दिनांक 3-5-2003 द्वारा दी गई मन्त्रणा में भी स्पष्ट किया गया है कि जिस कैडर में पदों की संख्या दो हो वहां भी आरक्षण का लाभ दिया जाना बनता है और इसके लिये रोस्टर रजिस्टर बनाया जाना होता है ।
- सरकार की हिदायतें क्रमांक 1549-2जी0एस0 I दिनांक 5-4-1977 तथा पत्र क्रमांक 22/40-83-3जी0एस0 III दिनांक 9-9-1983 के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये दैनिक वेतन, आकस्मिक श्रम तथा वर्क चार्ज की सेवाओं में भी आरक्षण लागू है ।

- सरकार की हिदायतें क्रमांक 1949-डब्ल्यू0जी0-54/23802 दिनांक 28-4-1954 तथा क्रमांक 22/21/81-3जी0एस0-III दिनांक 10-6-1982 के अनुसार स्थानान्तरण द्वारा भरे जाने वाले पदों में भी आरक्षण लागू है ।
- सरकार की हिदायतें क्रमांक 154-स0क0(1)-2002 दिनांक 6-2-2002 के अनुसार हरियाणा लोक सेवा आयोग/हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या अन्य किसी भी माध्यम से विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों से निर्धारित फीस तथा फार्म/प्रार्थना पत्र की कीमत का 1/4 भाग ही वसूल किया जाना है । इसी प्रकार तकनीकी/व्यवसायिक /शिक्षा संस्थाओं में दाखिले के लिये इन वर्गों के उम्मीदवारों से निर्धारित फीस/विवरण पत्रिका की राशि का 1/4 भाग लिया जाना है ।
- सरकार की हिदायतें क्रमांक 1016-4 डब्ल्यू0जी0-I-66/3774 दिनांक 16-2-1966 के अनुसार अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के जो कर्मचारी अन्यथा योग्य हों तथा उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है उन्हें तब तक नौकरी से हटाया या रिवर्ट नहीं किया जा सकता जब तक उनका प्रतिनिधित्व उनके लिये निर्धारित आरक्षण प्रतिशतता से अधिक न हो ।
- सरकार की हिदायतें क्रमांक 22/55/81-3जी0एस0-III दिनांक 15-3-1983 के अनुसार सीधी भर्ती में यदि निर्धारित अनुभव वाले अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध न हो तो ऐसे केस में 50 प्रतिशत तक अनुभव में छूट प्रदान की जा सकती है ।
- सरकार की हिदायतें क्रमांक 22/66/80-3जी0एस0-III दिनांक 18-7-1984 के अनुसार अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के जो कर्मचारी भूतपूर्व सैनिक के कोटे में भर्ती हुए हों, वे आगे दोनो प्रकार अर्थात् भूतपूर्व सैनिक तथा अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग का लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।
- सरकार की हिदायतें क्रमांक 22/66/81-3 जी0एस0-III दिनांक 1-10-1981 के अनुसार यदि अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग का उम्मीदवार निर्धारित भौक्षाणिक योग्यतायें तथा अनुभव पूर्ण करता हो, ऐसे उम्मीदवार का आरक्षित रिक्ति के विरुद्ध चयन न करने का कारण बताया जाना आवश्यक है ।
- सरकार की हिदायतें क्रमांक 22/28/89-3जी0एस0-III दिनांक 7-9-1989 के अनुसार यदि सीधी भर्ती के कोटे के विरुद्ध अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो ये रिक्तियां अन्य वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा नहीं भरी जा सकती तथा केवल विशेष परिस्थिति में ही जब श्रेणी एक के पद के विरुद्ध अनुसूचित जाति के योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न हों तथा लोकहित में उक्त पद खाली रखा जाना उचित न हो, की स्थिति में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सचिवों की बैठक में निर्णय लेने उपरान्त ही आरक्षित पद गैर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता है । इसके अतिरिक्त सरकार की हिदायतें क्रमांक

22/73/92-3जी.एस.-III दिनांक 14-10-1999 के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर0के0 सभ्रवाल बनाम पंजाब सरकार के केस में दिनांक 10-02-1995 को दिये गये निर्णय में निर्धारित कानून लागू करने के निदेश दिये गये हैं, जिसके अनुसार आरक्षित वर्गों के लिये निर्धारित रोस्टर बिन्दु आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा ही भरे जाने हैं तथा सामान्य वर्ग के उम्मीदवार आरक्षित बिन्दुओं पर नियुक्ति पाने के पात्र नहीं हैं ।

- सरकार की हिदायतें क्रमांक 2868-4डब्ल्यू0जी0-I-6जे0/13639 दिनांक 4-5-1966 के अनुसार अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के पीड़ित कर्मचारी अपनी शिकायत सीधे अपने विभागाध्यक्ष को भेज सकते हैं तथा इसकी एक अग्रिम प्रति अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा को भेज सकते हैं ।
- सरकार की हिदायतें क्रमांक 22/66/2000-3जी0एस0-III दिनांक 6-11-2001 के अनुसार अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित बैकलॉग की रिक्तियों पर 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा लागू नहीं होती है तथा 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा केवल वर्ष के दौरान सृजित होने वाली रिक्तियों पर लागू होती है व बैकलॉग की रिक्तियां एक अलग ग्रुप के रूप में भरी जा सकती है, जिन पर आरक्षण की कोई सीमा लागू नहीं होती ।
- सरकार की हिदायतें क्रमांक 6919-एस0डब्ल्यू0-1-72/21138-55 दिनांक 13-12-1972 के अनुसार राज्य सरकार के अधीन सभी सार्वजनिक उपक्रमों, वि विद्यालयों, स्वायत्त गासी संस्थाओं आदि में सीधी भर्ती तथा पदोन्नति में सरकार की आरक्षण नीति लागू करने के निदेश दिए गए हैं, जिन्हें समय-समय पर दोहराया भी गया है । हरियाणा सरकार की हिदायतें क्रमांक 22/3/81-3जी.एस.-III दिनांक 02-02-1981 द्वारा बोर्डों/निगमों/सहाकारी संस्थाओं/वि विद्यालयों/स्वायत्त गासी संस्थाओं आदि में राज्य सरकार की आरक्षण नीति की परिपालना करवाने की जिम्मेवारी संबंधित प्र गासकीय सचिवों को सौंपी गई है ।
- वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग के परिपत्र क्रमांक 22/17/95-शिक्षा-I(2) दिनांक 18-12-1996 के अनुसार सभी प्राईवेट मान्यता प्राप्त कालेजों में विभिन्न पदों की सभी कैटेगोरिज़ में अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के लिये सीधी भर्ती तथा पदोन्नति में सरकार की आरक्षण नीति लागू है ।
- आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग के परिपत्र क्रमांक 12/6/79-शिक्षा-II(4) दिनांक 17-10-1988 के अनुसार सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों में अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के लिये सरकार द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतों के अनुसार टीचिंग स्टाफ में सीधी भर्ती तथा पदोन्नति में आरक्षण लागू है ।
- सरकार की हिदायतें क्रमांक 3/3/99-I जी0एस0-III दिनांक 22-9-1999 के अनुसार सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्गों के लिये पांच वर्ष की छूट प्रदान की गई है ।

- सरकार की हिदायतें क्रमांक 22/10/2002-3जी0एस0-III दिनांक 16-3-2006 द्वारा राज्य में 85वां सविधान संशोधन लागू कर दिया गया है, जिसके अनुसार अनुसूचित जाति के कर्मचारी पदोन्नति में आरक्षण के आधार पर अर्जित की गई वरिष्ठता का लाभ उच्च पदों पर पदोन्नति के समय प्राप्त करने के पात्र हो गये हैं ।
- सरकार की हिदायतें क्रमांक 22/54/80-3जी0एस0-III दिनांक 5-2-1981 के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों व अन्य सभी आरक्षित वर्गों के लिये सेवाओं में आरक्षण सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने व आरक्षण सम्बन्धी रोस्टर रजिस्टर चैक करने की भाक्तियां अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा में स्थापित 'रोजगार सैल' को सौंपी गई हैं जो कि विभिन्न कार्यालयों के रोस्टर रजिस्टर चैक करके आरक्षण के सम्बन्ध में पाई गई कमियां दूर करने हेतु सम्बन्धित कार्यालयों को लिखता है तथा निरीक्षण के दौरान आरक्षण नीति के बारे में पाई जाने वाली त्रुटियों/कमियों के दृष्टिगत सरकार से हिदायतों में आव यक संशोधन करने बारे सिफारिश करता है । इन हिदायतों को पत्र क्रमांक 22/54/2000-3जी0एस0-III दिनांक 4-6-2001 द्वारा पुनः दोहराया गया है ।
- सरकार की हिदायतें क्रमांक 1170-एस0डब्ल्यू0(1)95 दिनांक 7-6-1995 के अनुसार पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ प्रदान करने के लिये किमीलेयर के मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं। सरकार की हिदायतें क्रमांक 22/36/2000-3जी0एस0-III दिनांक 9-8-2000 के अनुसार वेतनभोगीयों का वेतन आय के मापदण्ड में भामिल नहीं किया जाना है ।
- पुलिस महानिर्देशक, हरियाणा के पत्र क्रमांक 20511/ई(II)-2 दिनांक 28-09-2001 के अनुसार सिपाही के पद पर भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये 5 वर्ष की छूट है तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिये भारीरिक मापदण्ड में कद व छाती के नाप में एक-एक इंच की छूट है व भौक्षणिक योग्यता में भी छूट हैं ।

विभिन्न तकनीकी व्यावसायिक तथा भौक्षाणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण

- हरियाणा सरकार की हिदायतें क्रमांक 22/27/2004-3जी0एस0-III दिनांक 20-10-2005 के अनुसार विभिन्न तकनीकी/व्यावसायिक व भौक्षाणिक संस्थानों में दाखिले हेतु अनुसूचित जाति के लिये 20 प्रतिशत (10% ब्लाक 'ए' तथा 10% ब्लाक 'बी') तथा पिछड़े वर्गों के लिये 27 प्रतिशत (16% ब्लाक 'ए' तथा 11% ब्लाक 'बी') सीटें आरक्षित की गई हैं ।
 - सरकार की हिदायतें 3870-डब्ल्यू0जी0-I ए0एस0ओ0-II-64/20069 दिनांक 6/9-10-1964 के अनुसार विभिन्न संस्थानों में दाखिले के लिये अकों में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई हैं ।

नोट:- सेवाओं तथा दाखिले में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तथा इन वर्गों के लिए अन्य छूट सम्बन्धि मुख्य हिदायतों व जातियों की सूचियां संलग्न हैं ।

Instructions Regarding Reservation in Services

No.38/20/78-2GSI

From
The Chief Secretary to Govt. Haryana.

To

1. All Heads of Department,
Commissioners, Ambala & Hisar Divisions,
All Deputy Commissioners and
Sub Divisional Officers (Civil) in Haryana State.
2. The Registrar,
Punjab and Haryana High Court,
Chandigarh.

Dated, Chandigarh, the 9th February 1979.

Subject: **Reservation of posts for Scheduled Casts, Backward Classes and ex-servicemen under the services of Haryana State.**

Sir,

In supersession of Haryana Government instructions issued vide letter no.2812-2GS-I-76/11578, dated the 5th May, 1976, letter No.5074-2GSI-76/21898, dated the 17th August, 1976, and subsequent letter No.38/48/78-GSI, dated the 14th September, 1978 on the subject noted above. I am directed to say that the State Government has further reviewed on the existing policy of reservation of posts for Scheduled Castes, Backward Classes and Ex-servicemen in the services of Haryana and have decided as follows:-

(1) (i) The quantum of reservation will be as under:-

By Direct Recruitment

- (a) For Scheduled Castes 20% (in classes I, II, III and IV posts).
- (b) For Backward Classes 5% (-do-)
(Now 10% in class-I and II w.e.f. 18/9/1979 and 27% in class III & IV i.e. 16% block 'A' and 11% block 'B' w.e.f. 20/7/1995).
- (C) For Ex-servicemen
(i) 5% (in class I & II posts)
(ii) 25% (in class III and IV posts)
(Now 14% horizontal reservation i.e. 7% from Geneal, 2% from B.C. 'A', 3% from B.C. 'B', 1% from S.C. 'A' and 1% S.C. 'B' w.e.f. 26/7/2001 and now there is no vertical reservation for ESM in class – III & IV posts).

(ii) **BY PROMOTION**

- (a) For Scheduled Castes 20% (in class III and IV posts) on the basis of seniority/cum-merit.
(Reservation is also available in seniority cum fitness as per instruction dated 11-8-1988). There will be no reservation in Class I and II posts.
- (b) For Backward Classes 5% (-do-) (Withdrawn w.e.f. 16-11-1997 vide instruction dated 16-6-1998)
- (C) For Ex-servicemen Nil

(iii) Henceforthwith, in a block of 100 posts in each cadre, the following posts should be reserved for persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes and Ex-servicemen:

- (a) For persons belonging to Scheduled Castes (for direct recruitment to all classes of posts i.e. Class I, II, III and IV and for promotion to Class III and Class IV posts on the basis of selection from a slab of 3 officials).

4-8-14-18-24-28-34-38-42-50-54-58-64-68-74-78-84-88-92 and 100.

(Vide instructions dated 20-7-1995 in Class III and IV in direct posts roster point No. 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65, 70,75,80,85,90,95,100. For direct recruitment in class I & II and promotion quota posts in class III & IV roster points will be unchanged).

- (b) For persons belonging to Backward Classes (for direct recruitment to all

classes of posts and for promotion to class III and IV posts on the basis of selection from a slab of 3 officials)

16-32-46-70 and 94. (Now 10 points as shown in instruction dated 20-7-1995 and 26-7-2001).

(There is no reservation in promotion for Backward Classes w.e.f. 16/11/1997).

- (c) For Ex-servicemen:
(For Direct Recruitment to class I and II posts)
12-36-52-72 and 96

(For direct recruitment to class III and IV posts)

2-6-10-12-20-22-26-30-36-40-44-48-52-56-60-62-66-72-76-80-82-86-90-94- and 98. (Now 14% horizontal reservation and there is no vertical reservation w.e.f. 20/7/1995).

It is clarified that a single roster of 100 posts both for direct recruitment and promotion will be prepared as referred to above. This roster will continue from year to year till it is exhausted and thereafter a new roster will be prepared.

The aforesaid benefit of reservation will be given till such time as the number of employees belonging to reserved categories in each cadre/grade does not come upto the prescribed percentage.

- (2) When a requisition for the reserved posts, in accordance with sub-para (i) (ii) above, is sent to the Haryana Public Service Commission/Subordinate Services Selection Board, it shall advertise the same. If as a result of this advertisement, suitable candidates for the reserved posts are not available, then these posts shall be re-advertised immediately by the Haryana Public Service Commission/Subordinate Service Selection Board, as the case may be, without awaiting a further reference from the concerned Department. If suitable candidates are not available even on the basis of the second advertisement then the Commission/Board shall immediately re-advertise the posts for the third time indicating therein that if candidates belonging to the reserved categories are not available, the posts shall be filled by candidates belonging to the general category. This process shall be completed by the Commission/Board within the shortest possible time so that the reserved posts may not remain vacant for an unnecessarily long period. In respect of the posts on which candidates having technical and specialized qualifications are to be appointed, if suitable candidates are not available on the basis of the first advertisement, the Commission/Board shall re-advertise the posts immediately for the second time indicating therein that, if candidates belonging to reserved categories are not available, the posts shall be filled by candidates belonging to the general category. The Commission/Board shall keep the concerned Department informed of these advertisements.
- (3) Reserved posts not filled by the candidates belonging to reserved categories should be carried forward for two recruitment years. The recruitment year shall mean a calendar year and the two years limit for carry-forward of reserved posts shall start from the year in which recruitment is actually made. The carry-forward would mean that if a sufficient number of suitable candidates eligible for reserved posts are not available from the appropriate classes in any year of recruitment, such posts should be treated as un-reserved and filled in as un-reserved posts but should be carried forward to subsequent years of recruitment so that posts then occurring may be filled in by the persons belonging to reserved categories. For example, if a requisition for filling up of five posts of clerks, is sent to the Subordinate Services Selection Board in the month of January, 1977 and the recommendations of the Board are received in March, 1978 but the Board could not recommend any candidate against the reserved post, then the reserved posts would be carried forward for a period of two years viz 1979 and 1980. In this connection, it is further clarified that, in future, the carried forward reserved posts would be available togetherwith the current posts for utilization even when the total number of such reserved posts exceeds 50% of the posts filled in that year provided that the overall representation of Scheduled Castes/Backward Classes in the total strength of the concerned cadre does not exceed the prescribed percentage of reservation.

- (4) In case a single post arises in the initial recruitment year and it falls at a reserved point in the roster, it has to be treated as unreserved and filled accordingly in that year but the reservation would be carried forward to subsequent years. In the first subsequent year if again a single posts occurs then it should be treated as reserved against the reservation carried forward from the initial recruitment year and a candidate from the reserved category should be appointed against that post inspite of the fact that the post happens to be the only post in that recruitment year. In the event of a candidate belonging to reserved categories not being available to fill the reserved post in the subsequent year also, the reservation should be carried forward further to the subsequent year. When also a single post, if any, arises in that year it should be treated as reserved against the carried forward reservation whereafter the reservation will lapse e.g. a single vacancy occurs in any cadre of a particular department of the State which falls at a reserved point, that single post shall not be treated as reserved. But the single subsequent vacancy shall be treated as reserved and in case a candidate (belonging to scheduled Castes) for the reserved seat is not available the post shall be treated as reserved for the next two years under the carry-forward formula. The year in which no post arises is to be ignored for the purpose of counting the effective year towards the period of carry forward.

(According to instruction dated 7-9-1989 direct quota posts reserved for Scheduled Castes can not be filled by other then Scheduled Castes and according to instruction dated 14/10/1999, the law lay down by the Hon'ble Supreme Court in R.K. Sabharwal Vs. State of Punjab in its judgment dated 10/2/1995 is to be implemented according to which when a percentage of reservation is fixed in respect of a particular cadre and roster indicates the reserve points, it has to be taken that the posts shown at the reserve points are to be filled amongst the members of reserved catagories and the candidates belonging to general category are not entitled to be considred for the reserve posts).

- (5) "The reservation should be given both against the new post, whether permanent as well as aginst vacancies which may occur as a result of death, retirement, regisnation, removal, dismissal or promotion on regular basis" (Amended vide instructions dated 8-5-1980).
- (6) In the case of posts to be filled up by way pf promotion the benefit of reservation should be given where the basis of promotion is seniority-cum-merit and the benefit of reservation should not be made available where promotion is to be given on the basis of seniority-cum-fitness. (This para has been withdrawn vide instruction dated 11-8-1988).
3. These instructions should be brought to the notice of all concerned working under you

- for strict compliance.
4. Receipt of this communication may kindly be acknowledged.

Sd/-
Deputy Secretary, General Administration,
For Chief Secretary to Government, Haryana.

A copy is forwarded to:

1. Financial Commissioner, Haryana.
2. All Administrative Secretaries to Govt. Haryana, for information and necessary action.

Sd/-
Deputy Secretary General Administration,
For Chief Secretary to Government Haryana.

To

1. Financial Commissioner, Haryana.
2. All the Administrative Secretaries to Govt. Haryana.

U.O.No.38/20/78-2GSI, dated, Chandigarh, the 9th February, 1979.

Note:- 1. Quantum of reservation for Backward Classes, Ex-serviceman and roster points for different categories have been changed vide instruction dated 20-7-1995, 26-7-2001. Please see those instructions also.

No. 22/36/95-3GS-III

From: The Chief Secretary to Govt. Haryana.

To

All heads of Departments.

- ii. Commissioners Ambala/Hisar/Rohtak & Gurgaon Division.
- iii. All Deputy Commissioner & Sub-Divisional officers (Civil) in Haryana.
- iv. The Registrar Punjab & Haryana High Court.

Dated Chandigarh the 20th July 1995.

Sub:- Reservation for Scheduled Castes , Backward Classes (Block' A' & Block 'B'), Ex-servicemen & Physically Handicapped persons in direct recruitment to Class-III and Class –IV Govt. Jobs.

Sir,

Marg in No.38/20/78-2GSI Dated 09.02.79 No. 4/12 /779-GS III dated 18.09.79
No.34/7/80-

3GSIII dated 16.12.80 No. 2/20/83 -GSIII dated 26.11.85 No. 4/1/90- 3GSIII dated
20.02.90 No. 22/36/90 -3GSIII dated 24.01.91

1. I am directed to invite your attention to Haryana Govt. letters as indicated in the margin on the subject noted above and to say that in view of the directions given by Hon'ble Supreme Court of India in writ petition (Civil) No. 930 of 1990, Indira Sawhney & Others V/s Union of India and on the recommendations of the Second Backward Classes Commission setup by the Haryana Govt. the State Govt. has further reviewed the existing policy of reservation of posts for SC,BC, ESM and Physically handicapped in Govt. jobs in the State o Haryana and have decided to enhance the reservation for backward classes from 10% to 27% in respect of direct recruitment to Class-III and Class-IV posts.
2. It has further been decided to create two blocks i.e. Block 'A' and Block 'B' within the Backward Classes for the purpose of the above mentioned reservation as per list enclosed.

3. Henceforth the quantum of reservation for various categories in direct recruitment to Class III & IV posts will be as under:-

i.	SC	20%
ii.	BC (Block 'A')	16%
iii.	BCB (Block 'B')	11%
iv.	ESM/Dependents of ESM	10%
v.	Physically Handicapped	3%

(orthopedically handicapped , Deaf & Dumb and Blind)

The posts reserved for (Block 'A') of Backward Classes would be filled up from candidates belonging to castes of (Block 'A') only .Similarly posts reserved for (Block 'B') would be filled up from members of the castes comprising (Block 'B') of Backward Classes.

4. The reservation for ESM & Physically Handicapped will be horizontal reservation under Article 16(1) of the Constitution of India in respect of Class III & IV direct recruitment quota posts.

5. Horizontal reservation of 10% for ESM would be adjusted as below:-
3% in (Block 'A') of Backward Classes.
3% in (Block 'B') of Backward Classes.
4% in General Category.

Horizontal reservation of 3% for physically handicapped persons would be adjusted as below.

1% in (Block 'A') of BC

1% in (Block 'B') of BC

1% in General Category.

6. In the light of the revised quantum of reservation in respect of Class III and Class-IV direct recruitment quota posts, the roster points for reservation for different categories in a block of 100 posts in each/ Cadre would now be as follow.

SCHEDULED CASTES:-

5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100.

BACKWARD CLASSES:-

(Block 'A')

6-12-19(ESM)-26-32-38-44(ESM)-49-56-62(PH)-68-74 (ESM)79-86-92-99.

(Block 'B')

9-18-27(ESM)-36-46-54(ESM)-63-72-81(ESM)-89(PH)-98.

ESM (Ex-serviceman)

8 against General Category, 19 against B.C.((Block 'A')

27 against B.C. (Block 'B'), 37 against General category.

44 against B.C. (Block 'A'), 54 against B.C. (Block 'B').

64 against General Category, 74 against B.C. (Block 'A')

81 against B.C. (Block 'B') * 91 against General category.

PHYSICALLY HANDICAPPED:-

33 against General Category, 62 against B.C. (Block 'A') & 89 against B.C. (Block 'B') (Now 33,66,97 vide instructions dated 14/10/1997 and reservation is given vertical).

General Category:-

1-2-3-4-7-8(ESM) -11-13-14-16-17-21-22-23-24-28-29-31-33(PH)-34-37(ESM)-39-41-42-43-47-48-51-52-53-57-58-59-61-64(ESM)-66-67-69-71-73-76-77-78-82-83-84-87-88-91(ESM)-93-94-96 &97.

7. The position of reservation in respect of Class I & II posts will remain undisturbed, Roster points already prescribed with regard to Class I & II posts will, therefore, remain the same.
8. Similarly in respect of Class III & IV promotion quota posts the existing quantum of reservation will continue and therefore , the existing roster points will continue to remain in force.
9. The categorization of BC in to (Block 'A') & (Block 'B') will apply only in respect of direct recruitment to Class III & IV posts. All the BC notified as eligible for reservation benefit by Social Welfare department from time to time will be treated as one category for the purpose of reservation benefit in respect of direct recruitment in Class I & II posts and promotion in Class III & IV posts.
10. Henceforth there would be no division of reservation meant for physically handicapped into orthopaedically handicapped, deaf & dumb and blind categories in case of direct recruitment to Class III & IV posts. For this purpose, all physically handicapped persons will be treated as one category.
11. As regards carry forward/dereservation of the posts reserved for various categories, the existing instructions would continue to be in force.

12. Instructions issued vide letter No. 1170-SW(I)—95 dated 07.06.1995 by the Welfare of SC & BC Department regarding exclusion of Socially advanced persons/sections (Creamy Layer) should be kept in view while extending the benefit of reservation to BC.
13. These instructions may kindly be brought to the notice of all concerned working under you for strict compliance.

Receipt of this communication may be acknowledged.

Yours faithfully,
Sd/-
Joint Secretary , General Adm.
for Chief secretary to Govt. Haryana.

A copy each is forwarded to :-

1. All Financial Commissioners to Govt. Haryana.
2. All Administrative Secretaries to Govt. Haryana for information & necessary action.

Sd/-
Joint Secretary , General Adm.
for Chief secretary to Govt. Haryana

To

1. All Financial Commissioners to Govt. Haryana.
2. All Administrative Secretaries to Govt. Haryana.

U.O.NO. 22/36/95-3GS-III Dated 20.07.1995.
Endst No. 22/36/95-3GS-III Dated 20.07.1995.

A copy is forwarded to the Secretary , Haryana Public Service Commission, Chandigarh & Secretary, Subordinate Services selection Board, Haryana, Manimajra for information & necessary action.

Sd/-
Joint Secretary , General Adm.
for Chief secretary to Govt. Haryana

Note:- 3% vertical reservation has been provided for Physically Handicapped i.e. 1% Orthopadically Handicapped, 1% for Deaf & Dumb and 1% for blind vide Govt. instruction No. 22/96/96-3GSIII dated 14/10/1997.

1. Copy of letter No. 22/15/92-3G.S.III dated 26.07.2001 from the Chief Secretary to Govt. Haryana. To All Heads of departments.

2. Commissioners Ambala/Hissar/Rohtak & Gurgaon divisions.

3. The Registrar Punjab & Haryana High Court , Chandigarh

4. All Deputy Commissioner & Sub-Divisional officers (Civil) in Haryana State.

Sub:- Reservation of jobs for outstanding sport persons in Group 'C' & 'D' in direct recruitment.

Sir,

1. I am directed to refer to Haryana Govt. letter no. 22/36/95-3G.S.III dated 20.07.1995 and letter No. 22/19/99-3G.S.III dated 14.07.2000, on the subject noted above, vide which the horizontal reservation for E.S.M. was originally provided at the ration of 10% & subsequently enhanced to 15% in direct recruitment to Class-III & IV posts.

2. The matter regarding reservation for outstanding sports persons in Govt. service had been under consideration of the State Govt. for some time and it has been decided to provided 3% horizontal reservation in direct recruitment in Govt. jobs in Group 'C' & 'D' . By doing this the total horizontal reservation will increases from 15% to 17% . Revised horizontal reservation for E.S.M. as well as the outstanding sports persons will be adjusted as under:-

Sr.No.	Category	Percentage of Reservation
1.	2.	3.
1.	S.C.(A)	1% for E.S.M.
2.	S..C.(B)	1% for E.S.M.
3.	B.C.(A)	2% for E.S.M.
4.	B.C.(B)	3% for E.S.M.
5.	General Category	7% for E.S.M.
6.	S.C. (A& B)	1% by rotation for outstanding sports persons of A&B category of S.C.

7.	B.C. (A&B)	1% by rotation for outstanding sports persons of A&B category of B.C.
8.	General category	1% for general category of outstanding sports persons

3. In view of 3% horizontal reservation in direct recruitment to the outstanding sports persons in Group 'C' & 'D' posts, the roster points for reservation from different categories in a block of 100 posts in each cadre would now be as follows:-

i. Scheduled Castes (A&B)- 1% by rotation

The roster point 25 should be given to SC category of outstanding sports persons by rotation i.e. in a block of 100 roster points only 1% will be given to S.C. category.

ii. Backward Classes (A& B)-1% by rotation

In a block of 100 posts, the roster point No.32 will be given to block 'A' of B.C. Category of outstanding sports persons. Similarly in a block of next 100 posts, the roster point no. 63 will be given to B.C. 'B' category of outstanding sports persons by rotation.

iii General Category-1%

Roster Point No. 91 meant for E.S.M. of General Category, now will be given to outstanding sports persons of general category.

These instructions may kindly be brought to the notice of all concerned working under you for compliance.

Yours faithfully,

Sd/-

Under Secretary General Administration

for Chief Secretary to Government Haryana.

क्रमांक 1549-2जी0एस0-1-77 / दिनांक 05-04-1977

प्रेषक मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,

- सेवा में (1) हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी ।
(2) रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट तथा हरियाणा के सभी जिला तथा सत्र न्यायाधी ।
दिनांक चण्डीगढ़ 5 अप्रैल, 1977

विशय:- अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों को आकस्मिक श्रम में आरक्षण देना ।

महोदय,

उपरोक्त विशय पर आपको सम्बोधित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि हरियाणा राज्य में वर्तमान जारी की गई हिदायतों के अनुसार सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों को निम्नलिखित आरक्षण प्रदान किया जाता है:-

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| (1) अनुसूचित जातियों के लिये | 20% |
| (2) पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये | 2% |

2- वर्तमान नीति के अनुसार अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों को राज्य सरकार के विभागों में दैनिक तथा मासिक तौर पर भर्ती की जाने वाली आकस्मिक श्रम को भर्ती के समय आरक्षण नहीं दिया जाता है । इसलिये इस मामले को विचारने के उपरान्त सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों को यथा सम्भव राज्य सरकार के सभी विभागों द्वारा दैनिक तथा मासिक तौर पर भर्ती की जानी वाली आकस्मिक श्रम में भी आरक्षण ऊपर पैरा-1 में बताये गए प्रतिशत के हिसाब से दिया जाए ।

3- यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त हिदायतों को कठोरता से पालन किया जाए तथा सभी सम्बन्धित कर्मचारियों के नोटिस में लाया जाए ।

भवदीय,

हस्ता / -0

उप-सचिव, सामान्य प्रसासन

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति निम्नलिखित :-

- (1) वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा सरकार ।
- (2) सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

को सूचनार्थ तथा आवक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है ।

हस्ता / -0

उप-सचिव, सामान्य प्रसासन

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

- सेवा में (1) वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा सरकार ।
(2) सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अ 110 क्रमांक 1549-2जी0एस0-1-77 / दिनांक 5-4-1977

Copy of letter No. 22/40/83-GSIII dated 9th September, 1983 from the Chief Secretary to Govt. Haryana to all the Heads of Deptts. Commissioners Ambala & Hisar Divison, All Deputy Commissioner and Sub-Divisional Officers (Civil) in Haryana. The Registrar, Punjab and Haryana High Court and all district & Session Judge in Haryana.

Subject:- Reservation of work-charge posts for the Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen and Physically handicapped.

Sir,

I am directed to state that the question whether the benefit of reservation should be given to the reserved categories of persons in respect of work-charged posts also, has been engaging the attention of the State Govt. for some time past. It has now been decided that the work-charged posts should also be reserved for these persons as under:-

- | | | |
|-----|---|----------------------------|
| (a) | For Scheduled Castes | 20% |
| (b) | For Backward Classes | 10% |
| (c) | For Ex-servicemen | 17% |
| (d) | For physically handicapped i.e. the blind the deaf & dumb and the Orthopadically handicapped. | 3% (1% for each category). |

The other instructions issued vide circular letter No. 24/17/80-3GSIII dated 16-12-80. Will also apply to the reservation of work-charged posts.

2. These instructions may please be brought to the notice all concerned for compliance.

WELFARE DEPARTMENT, HARYANA

Endst. No. BC/SA/83/

Dated Chandigarh, the

1. All the District Welfare Officer, in Haryana State.
2. Principal, Pre-Examination Training Centre, Ambala, Rohtak and Bhiwani.

Sd/-

Statistical Officer,
for District, Welfare of Scheduled Castes
and Backward Classes Department, Hr.
Chandigarh.

No. 22/93/2002-3GSIII

From
The Chief Secretary to Govt. Haryana.

To

- i. All Heads of Departments, Commissioners, Ambala, Hisar, Rohtak & Gurgaon.
- ii. The Registrar Punjab & Haryana High Court, Chandigarh.
- iii. All Deputy Commissioner & Sub-Divisional Officers (Civil) in Haryana.

Dated Chandigarh the 3rd June, 2002.

Sub:- Reservation of posts for Scheduled Castes & Backward Classes/Ex-serviceman under the services of Haryana State.

Sir,

1. I am directed to refer to Haryana Government letter No. 38/20/78-2GSI, dated 09.07.79 on the subject noted above and say that vide this State of Haryana formulated a policy of reservation. Main feature of the policy is that roster points of 100 posts was adopted and roster points of Scheduled Castes & Backward Classes/Ex-serviceman were fixed for their reservation. The roster points are being followed in promotion to the employee of Scheduled Castes category in Class-III and IV posts.
2. Hon'ble Supreme court of India in Civil Appeal No. 4480 of 1990-S.R. Murthy V/s State of Karnatka and Ors. and in other judgment delivered by Supreme Court of India on Post Graduate Institute of Medical & Research Chandigarh V. Faculty Association and Ors JT 1998 (3) SC223 1998 (2) SLR 765 (SC) case held that there can not be any reservation in a single cadre post and application of roster for purpose of reservation in promotion/recruitment is not permissible and on the other hand the roster in reservation can operate if there is plurality of the posts in the cadre.
3. In view of the aforesaid judgments of Hon'ble Supreme Court and a reference from Law Department, the matter has been carefully examined and it has been decided that there will be no reservation in single cadre post either directly or by device of rotation of roster point and on the other hand the roster in reservation can operate if there is plurality of the posts in the cadre.

4. These instructions may kindly be brought to the notice of all concerned working under you for compliance.

Yours faithfully,

Sd/-

Under Secretary General Administration
for Chief Secretary to Government Haryana.

A copy is forwarded to all the Financial Commissioners & Principal Secretary and all the Administrative Secretaries to Govt. Haryana for information & necessary action:-

sd/-

Under Secretary General Administration
for Chief Secretary to Government Haryana.

To

All Financial Commissioners & Principal Secretaries
& All Administrative Secretaries to Govt. Haryana.

U.O.NO. 22/93/2001-3GS-III Dated Chandigarh, the 3rd June,2002

A copy is forwarded to all the Branch Officers/ Superintendent /Deputy Superintendent of Chief Secretary/F.C. office for information & necessary action.

sd/-

Under Secretary General Administration
for Chief Secretary to Government Haryana

To

All the Branch Officers/ Superintendent /Deputy Superintendent of Chief
Secretary/F.C. office

U.O.NO. 22/93/2001-3GS-III Dated Chandigarh, the 3rd June,2002

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,

सेवा में

निदेशक,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

यादि क्रमांक 22/63/2000-3 जी०एस०-III
दिनांक 05-03-2003

विशय:- श्रेणी I, II, III तथा IV के पदों में विकलांगों को आरक्षण प्रदान करने बारे मन्त्रणा ।

1- उपरोक्त विशय पर आपके यादि क्रमांक ए०आर०आई०ई०/2000/19470 दिनांक 18-8-2000 तथा ई०सी० 57/445 दिनांक 27-2-2003 के सन्दर्भ में ।

2- इस सम्बन्ध में आपका ध्यान सरकार द्वारा जारी हिदायतें दिनांक 9-2-79 तथा 3-6-2002 की ओर दिलाया जाता है तथा सूचित किया जाता है कि जिस काडर में पदों की संख्या दो भी हो वहां पर भी आरक्षण का लाभ दिया जाना बनता है इसके लिये रोस्टर रजिस्टर बनाया जाना होता है ।

हस्ता०/-

अधीक्षक, सामान्य सेवाये-III
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

No. 22/66/2000-3 G.S. III

From
The Chief Secretary to Government
Haryana, Chandigarh.

To

1. All Head of the Departments, Commissioners Ambala, Hisar, Gurgaon and Rohtak Divisions.
2. The Registrar, Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.
3. All Deputy Commissioners and All Sub-Divisional Officers(Civil) in Haryana State.

Dated, Chandigarh, the 6th Nov., 2001.

Subject: - Treatment of backlog vacancies reserved for SCs and STs as a distinct group and non- applicability or 50% ceiling thereon.

Sir,

I am directed to refer to Haryana Government Instructions No. 22/79/95-3G.S.-III dated 12.9.79 and 21.8.2000 on the subject noted above regarding filling of backlog in the reserved vacancies- Supreme court judgment in Indira Sawhney writ petition(Civil) No. 930/90 case and to say that in view of the 81st amendment made by the Parliament in the Constitution of India, the necessary instructions were issued by the Govt. of India, Ministry of personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel and Training Estt. Reservation (Section) on 20.7.2000. Consequently Article 16(4B) has been incorporated in the constitution by the constitution(Eighty first Amendment) Act. 2000, which provides as under:-

“ Nothing in this article shall prevent the State from considering any unfilled vacancies of a year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision for reservation made under clause(4) or Clause(4A) as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years and such class of vacancies shall not be considered together with the

vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of fifty percent reservation on total number of vacancies of that year.”

In pursuance of the provisions of Article 16(4B) of the constitution, it has been decided by the State of Haryana that the reserved vacancies for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in all cases of direct recruitment and promotion, wherever applicable, which have remained unfilled in the earlier year(s) i.e. backlog and/or carried forward vacancies would be treated as a separate and distinct group and will not be considered together with reserved vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies of that year. In other words, the ceiling of 50% on filling up of reserved vacancies would apply on the reserved vacancies which arises in the current year and the backlog/carried forward reserved vacancies for SCs/STs of earlier years would be treated as a separate and distinct group and would not be subject to any ceiling. However, backlog and/or carried forward reservation will automatically lapse in a cadre as soon as combined representation of a reserved category in direct recruitment as well as promotion is either equal to or more than the prescribed number of reserved posts in the relevant post-based rosters.

The above instructions may please be brought to the notice of all concerned for strict compliance.

Yours faithfully,

Sd/-

Under Secretary General Administration
For Chief Secretary to Government,

Haryana.

A copy is forwarded to all the Financial Commissioners and Administrative Secretaries to Govt. Haryana for information and necessary action.

Sd/-

Under Secretary General Administration
For Chief Secretary to Government, Haryana.

To

1. All the Financial Commissioners in Haryana State.
2. All the Administrative Secretaries to Govt. Haryana

U.O.No. 22/66/2000/3GS III

Dated 6.11.2001

Endst. No. 22/66/2000/3GS III

Dated 6.11.2001

A copy is forwarded to Member Secretary, Haryana Bureau of Public Enterprises for information and necessary action. They are requested to send the copy of these instructions to all the Boards/Corporations in the State of Haryana for taking necessary action.

Sd/-

Under Secretary General Administration
For Chief Secretary to Government, Haryana.

Reservation Of Posts For Scheduled Castes, Backward Classes Under The Service Of Haryana State (85th Amendment)

No.22/10/2002-3GSIII

From
The Chief Secretary to
Government Haryana.

To

1. All Head of Department, Commissioner, Ambala, Rohtak, Gurgaon & Hisar Divisions.
2. The Registrar, Punjab & Haryana High Court, Chandigarh
3. All the Deputy Commissioners & Sub Divisional Officer (Civil) in Haryana State.

Dated Chandigarh, the March 16,2006

Subject: Reservation of posts for Scheduled Castes, Backward Classes under the services of Haryana State. (85th Amendment)

Sir,

1. I am directed to refer to the instructions issued by the Government vide letter No.22/73/92-3GSIII, dated the 14th October, 1999 on the subject noted above whereby the departments were conveyed the operative parts of the law laid down by the Hon'ble Supreme Court of India in its judgement dated 16-9-1999 in the case of Ajit Singh Janjua Versus State of Punjab and directed that from the date of two judgements i.e. R.K.Subharwal (Decision dated 10-2-95) and Ajit Singh Janjua (Decision dated 1-3-96) no employee belonging to the reserved categories of scheduled castes or backward classes should be allowed the benefit of accelerated seniority over his/her senior belonging to General Category on account of his/her accelerated promotion from the feeder services under the policy of reservation. Accordingly, the departments were further directed to implement the law laid down by the Apex Court, keeping in view the principle of prospectively of R.K. Sabharwal and Ajit Singh as decided in the aforementioned judgement dated 16-9-1999.
2. The Government of India has notified the Constitution (Eighty Fifth) Amendment Act, 2001 on 4-1-2002 amending Article 16(4-A), which now reads as under:-
"Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for reservation in matter of promotion with consequential seniority to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and

Scheduled Tribes which, in the opinion of the State are not adequately represented in the services under the State”.

3. In the wake of the above enabling provision, after careful consideration of the matter, it has been decided by the State Government that the Scheduled Castes employees will be entitled to “accelerated seniority” as a consequence of promotions under the reservation policy.
4. This decision shall come into force with immediate effect and shall have prospective effect only.

These instructions should be brought to the notice of all concerned for being adhered to strictly.

Yours faithfully

Sd/-

Deputy Secretary General Administration
For Chief Secretary to Government Haryana.

A copy is forwarded to all the Financial Commissioners and Principal Secretaries/Commissioners and Secretaries to Government Haryana for information and necessary action.

sd/-

Deputy Secretary General Administration
For Chief Secretary to Government Haryana.

To

All the Financial Commissioners and Principal Secretaries/Commissioners & Secretaries to Govt. Haryana.

U.O.No.22/10/2002-3GS-III
Endst.No.22/10/2002-3GS-III

Dated Chandigarh, the March 16,2006
Dated Chandigarh, the March 16,2006

A copy is forwarded to the Member Secretary, Haryana Bureau of Public Enterprises, Chandigarh with the request to bring these instructions to the notice of all the Boards/Corporations and Public Undertakings for information/necessary action and strict compliance.

sd/-

Deputy Secretary General Administration
For Chief Secretary to Government Haryana.

Adoption of policy of reservation for recruitment in private affiliated colleges.

Copy of letter No.22/17/95-Edu-I (2) dated 18-12-1996 from the Financial Commissioner & Secretary to Govt. Haryana, Education Department to the Director of Higher Education, Haryana, Chandigarh.

Subject: Adoption of policy of Reservation for recruitment in Private Affiliated Colleges.

The matter regarding adoption of reservation policy of Government in Private affiliated colleges for Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes in recruitment has been under consideration of the Government for some times. Government have carefully considered the matter and have come to the conclusion that the State Govt. meets 95% of the deficit of salary of the staff appointed against sanctioned posts in the shape of Grant-in-aid. According to the conditions of Grant-in-aid contained in Govt. letter No.43/3/65-Edu-I(2) dated 28-8-92, the private affiliated colleges receiving grant-in-aid have to comply with the orders or directives issued by the Govt. from time to time in both letter and spirit.

In view of the above decision, Govt. have decided that the Reservation Policy of the Govt. issued vide letter No.38/20/78-2GSI dated 9-2-79 and letter No.22/36/95-3GSII dated 20-7-95 (copies enclosed) for recruitment in services may be followed by the Private Affiliated Colleges for recruitment to the various posts of all categories in these colleges. The brief description of the quantum of reservation in posts/services as per reservation policy

contained in the above letters will be as under:-

By direct recruitment and by promotion

- | | | | |
|----|---|---|----------------|
| 1. | For Scheduled Castes | : | 20% |
| 2. | For Backward Classes
(Block A & B) | : | 27%(16% & 11%) |
| 3. | ESM/Dependents of ESM | : | 10% |
| 4. | Physically handicapped
(orthopaedically handicapped,
Deaf & Dumb and blind) | : | 3% |

For detail description the attached policy letters issued by the Govt. on this subject from time to time should be consulted.

In case of non-compliance of the reservation policy by any of the affiliated colleges, suitable action would be taken against that college. This policy would be applicable for all categories of employees i.e. teaching/non-teaching, technical/non-technical with immediate effect against vacant posts. This policy will be compulsory for all affiliated colleges.

This be brought to the notice of all affiliated colleges in the State.

Office of the Director of Higher Education, Haryana, Chandigarh.

Endst.No.1/4-82-C-II(3)

Dated, Chandigarh, the 10-3-97

A copy is forwarded to the following for strict compliance & necessary action in the matter:-

1. All the Principals of Non-Govt. Affiliated Colleges in the State of Haryana.
2. Dean of Colleges, Kurukshetra University, Kurukshetra.
3. Dean of Colleges, M.D. University, Rohtak.
4. Dean of Colleges, Guru Jambheshwar University, Hisar.
5. Superintendent Colleges-IV Branch. They should maintain the reservation record in appointment of teaching staff.
6. College-II/4(Local). For maintaining record in case of non-teaching posts.
7. Supdt. UNP (Local)

Sd/-

Deputy Director for College-II,
For Director of Higher Education,
Haryana, Chandigarh.

Policy of reservation for scheduled castes and backward classes in recruitment of staff in privately managed recognised schools.

Copy of letter dated 17th October 1988 from Commissioner & Secretary to Govt. Haryana, Education Department addressed to the Director of School Education, Haryana, Chandigarh and others.

No. 12/6/9-Edu.II(4):- The Governor of Haryana is pleased to incorporate the following clause in the article No. 214 of Haryana Education Code as item No. (Xviii) of the said article with immediate effect:-

“214 (Xviii) The reservation of 30% (20% for the members of Scheduled Castes/Tribes and 10% for the members of Backward Classes) in each of posts of teaching personnel of privately managed recognised Aided Schools to be filled through direct recruitment as well as against the posts to be filled by promotion should be made as per instructions issued of the Haryana Government from time to time as applicable to State Govt. Employees”.

Office of the director of secondary education, chandigarh.

Endst. No. 5/30-88-S.I(3)

Dated 29-05-89

A copy of the above notification is sent to all the District Education Officers in the State. They are directed that the directions contained in the notification may be brought in the notice of all the Heads of Privately managed Schools in their district for strict compliance.

Sd/-

Officer on Special Duty,
for Director of Secondary Education,
Haryana,

Chandigarh.

Endst. No.

dated : Chandigarh 29-5-89

A copy is forwarded to Director, Primary Education, Haryana, Chandigarh for information and necessary action.

Sd/-

Officer on Special Duty,
for Director of Secondary Education, Haryana,
Chandigarh.

प्रेषक

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग !

सेवा में

- 1) सभी विभागाध्यक्ष हरियाणा राज्य में
- 2) आयुक्त अम्बाला, हिसार, रोहतक तथा गुड़गांवा मण्डल !
- 3) सभी उपायुक्त हरियाणा राज्य में !
- 4) सभी उप मण्डल अधिकारी (ना0) हरियाणा राज्य में !
- 5) रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय !

दिनांक 28.09.1995

विशय: अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिये तकनीकी, भौक्षणिक तथा व्यवसायिक संस्थाओं में दाखिले के लिए आरक्षण ।

श्रीमान् जी,

3. मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपरोक्त विशय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के पत्र नं0 1872—स0क0—1/81, दिनांक 8—7—1981 की ओर आकर्षित करूं !
4. मण्डल आयोग एवं हरियाणा द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिशों के दृष्टिगत पिछड़े वर्गों को तकनीकी, भौक्षणिक तथा व्यवसायिक संस्थानों के दाखिले में उचित प्रतिनिधित्व देने का मामला सरकार के विचाराधीन था तथा विचारोपरान्त राज्य सरकार ने तकनीकी, भौक्षणिक तथा व्यवसायिक संस्थानों में दाखिले में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है !
5. इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त आरक्षण का लाभ देने हेतु पिछड़े वर्गों को दो खंडों में रखा जाये अर्थात् खण्ड ए तथा खण्ड बी (सूची सलंगन) खण्ड ए जिसमें 67 पुरानी जातियां हैं उनके लिए आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत होगा तथा खण्ड बी जिनमें नई जो 5 जातियां शामिल की गईं हे उनके लिये 11 प्रतिशत आरक्षण होगा !
6. सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि इस समय अनुसूचित जातियों के लिये जो 20 प्रतिशत आरक्षण है, उसको यथावत रखा जाये !

7. विभिन्न श्रेणियों के लिये आरक्षण निर्धारित करते समय इंदिरा साहनी तथा अन्य बनाम भारत सरकार सिविल रिट पटी नं० 930 आफ 1990 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये, का भी ध्यान रखा जाये।
8. आरक्षण का लाभ देते समय पिछड़ी जातियों में सम्पन्न वर्गो (creamy Layer) के बारे जो हिदायतों सरकार के पत्र नं० 1170-स०क०(1)-95, दिनांक 7-6-95 द्वारा जारी की गई हैं उनकी दृढ़ता से पालना की जाये।

हस्ता/-
संयुक्त सचिव,
कृते: आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग

एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचना तथा आवेदन कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

- 1 सभी वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार।
- 2 सभी प्रासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।

हस्ता/-
संयुक्त सचिव,
कृते: आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।

सेवा में

- 1 सभी वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार।
- 2 सभी प्रासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।

अ आ० क्रमांक 1883-स०क०(1)-95

दिनांक 28-9-95

नोट:-

उपरोक्त हिदायतों के अनुसार हरियाणा के सभी तकनीकी, भौक्षणिक तथा व्यवसायिक संस्थानो, कालेजों, स्कूलों तथा अन्य संस्थानों में दाखिले में आरक्षण है। यह आरक्षण नीति सभी सरकारी तथा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कर रहे गैर सरकारी प्राईवेट (Govt. Aided Private Affiliated) कालेजों तथा स्कूलों पर भी लागू है। यह हिदायतें सभी विविद्यालय में भी लागू है।

No. 22/27/2004-2GSII

From
The Chief Secretary to Govt. Haryana.

To

- v. All Heads of Departments in the Haryana State.
- vi. The Registrar Punjab & Haryana High Court, Chandigarh.
- vii. All Deputy Commissioner & Sub-Divisional Officers (Civil) in Haryana.

Dated Chandigarh the October 20, 2005.

Sub:- Reservation for admission in educational/professional colleges/Institutions.

Sir/Madam,

I am directed to invite your attention to Haryana Govt instructions issued vide letter No. 22/34/98-3GSIII, dated 19.03.99, followed by letters of even number dated 05.05.99 and letter No. 22/89/97-3GSIII, dated 07.08.2000 on the subject noted above, wherein provision for reservation of seats in the educational, technical and professional institutes for the candidates of various categories was made as under:-

1.	Scheduled Castes	20%	(50% each 'A' & 'B' Block)
2.	Backward Classes	16%	A Block
	Backward Classes	11%	B Block
3.	Physically handicapped	3%	In the event of quota reserved for physically handicapped remain unutilized due to non-availability for suitable category of handicapped candidate, it may be offered to the Ex-serviceman and their wards (1%) and the dependents of Freedom-fighters(1%)

On the further consideration of the matter, it has been decided to allow 3% horizontal reservations to Ex-serviceman /freedom-fighters and their dependents by providing reservation within reservation of 1% of general category, 1% out of scheduled castes and 1% from backward classes category for admission to the various educational institutions of the Govt. and Government aided/self financing colleges/institutions located in Haryana. As far as block allocation in Block A & B of Scheduled Castes & Backward Classes categories is concerned, year-wise rotational system will be adopted e.g. if blocks A of Scheduled Castes & Backward Classes are given seats in the academic year 2006, the next block i.e. B

Block of categories of Scheduled Castes & Backward Classes will be given seats in the next academic year i.e.2007 and so on.

These instructions should be brought to the notice of all concerned working under control for strict compliance.

Yours faithfully,

Sd/-

Deputy Secretary General Administration
for Chief Secretary to Government Haryana.

From

The Commissioner and Secretary to Govt.
Haryana, Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department,
Haryana, Chandigarh.

To

1. All Heads of Department, Commissioner, Ambala, Hisar, Rohtak and Gurgaon Divisions.
2. All Deputy Commissioners and Sub Divisional Officers (Civil) in Haryana.
3. The Registrar, Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.

No. 1170-SW(I)-95

Dated Chandigarh, the 07.06.1995

Subject:- Exclusion of socially advanced persons/sections (Creamy Layer) from Backward Classes.

Sir,

I am directed to invite your attention to the subject mentioned above and to state that following the Supreme Court judgement in the Indira Sawhney and Others versus Union of India case, the Haryana Government vide notification dated 12.10.1993 had set up the Haryana Second Backward Classes Commission. The terms of reference of this Commission were to entertain, examine and recommend upon requests for inclusion and complaints of over-inclusion and under-inclusion in the list of Backward Classes. Vide notification dated 26.5.1994, the Commission was also assigned the function of specifying the basis, applying the relevant and requisite socio-economic criteria to exclude socially advanced persons/sections (Creamy Layer) from Backward Classes.

In its report submitted on 16.5.1995, the Haryana Second Backward Classes Commission had recommended the criteria for excluding socially advanced persons/sections (Creamy Layer) from Backward Classes. After considering these recommendations, the Government has decided that the benefit of reservation shall not apply to persons/sections mentioned in Annexure "A" which is enclosed.

All the departments are requested to bring the above instructions to the notice of all the Heads of Departments and appointing authorities under their control for necessary compliance.

Yours faithfully,
Sd/-
Joint Secretary,
For Commissioner and Secretary to Govt.
Haryana, Welfare of Scheduled Castes
and Backward Classes Department.

Endst.No. 1170-SW(I)-95 Dated Chandigarh, the 7.6.95

A copy of each is forwarded for information to the :-

1. Secretary to Governor, Haryana.
2. All Ministers(including the Chief Minister) and the Ministers of State.
3. All Financial Commissioners and All Administrative Secretaries to Government, Haryana.
4. Secretary, Haryana Vidhan Sabha.

Sd/-
Joint Secretary,
For Commissioner and Secretary to Govt.
Haryana, Welfare of Scheduled Castes
and Backward Classes Department.

To

1. Secretary to Governor, Haryana All Ministers(including the Chief Minister) and the Ministers of State.
2. All Financial Commissioners and All Administrative Secretaries to Government, Haryana.
3. Secretary, Haryana Vidhan Sabha.

Sd/-
Joint Secretary,
For Commissioner and Secretary to Govt.
Haryana, Welfare of Scheduled Castes
and Backward Classes Department.

Annxure 'A'

Discription Of Category	To Whom Rule Of Exclusion Will Apply
1. Constitutional Posts	Son(s) and daughter(s) of <ul style="list-style-type: none">(a) President of India;(b) Vice President of India;(c) Judges of the Supreme Court and of the High Court.(d) Chairman and Members of UPSC and of the State Public Service Commission; Chief Election Commissioner; Comptroller and Auditor General of India;(e) Persons holding Constitutional positions of like nature
II. Service Category A- Group A/Class-1 Officers Of The All India Central And State Services(Direct Recruits)	Son(s) and daughter(s) of <ul style="list-style-type: none">(a) Parents both of whom are Class I Officer(b) parents, either of whom is a Class I Officer;(c) parents both of whom are Class –I officers, but one of them dies or suffers permanent incapacitation.(d) Parents, either of whom is a Class I Offier and such parent dies of suffers permanent incapacitation and before such death of such incapacitation has had the benefit of employment in any Inter National Organisation like U.N., I.M.F. world Bank etc. for a period of not less than 5 year(e) Parents, both of whom are Class I Officers dies or suffer permanent incapacitation and before such death or such incapacitation of the both, either of them has had been the benefit of employment in any international Organisation like U.N. I.M.F. World Bank, etc. for a period of not less than 5 years. <p>Provided that the rule of exclusion shall not apply in the following cases:-</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Sons and daughters of parents either of who or both of whom are Class-I Officers and such parent(s) dies/die or suffer permanent incapacitation.(b) A lady belonging to OBC category has got married to a Class-I Officer, and may herself like to apply for a job.
B. Group B/ Class II Officers of the Central	Son(s) and daughter(s) of <ul style="list-style-type: none">(a) Parents both of whom are Class II Officers.

and State Services(Direct Recruitment).

- (b) Parents of whom only the husband is a Class II Officer and he gets into Class I at the age of 40 or earlier.
- (c) Parents, both of whom are Class II Officers and one of them dies or suffers permanent incapacitation and either one of them has had the benefit of employment in any International Organisation like U.N., I.M.F., world Bank, etc. for a period of not less than 5 years before such death or permanent incapacitation;
- (d) Parents of whom the husband is a Class I Officer(direct recruit or pre-forty (promoted) and the wife is a Class II Officer and the wife dies; or suffers permanent incapacitation; and
- (e) Parents, of whom the wife is a Class I Officer(Direct recruit or pre-forty promoted) and the husband is a Class II Officer and the husband dies or suffers permanent incapacitation.

Provided that the rules of exclusion shall not apply in the following cases:-

Sons and daughters of

- (a) Parents both of whom are Class-II Officers and one of them dies or suffers permanent incapacitation.
- (b) Parents, both of whom are Class-II officers and both of them dies or suffer permanent incapacitation, even though either of them has had the benefit of employment in any International Organisation, like U.N., I.M.F., World Bank, etc. for a period of not less than 5 years before their death or permanent incapacitation.

C- Employees In Public Sector Undertakings Etc.

The criteria enumerated in A and B above in this category will apply mutatis mutandi to officers holding equivalent or comparable posts in PSUs, banks, Insurance Organisations, Universities etc. Pending the evaluation of the posts on equivalent or comparable basis in these institutions, the criteria specified in Category V below will apply to the Officers in these institutions.

III (Armed Forces

Sons and daughter(s) of

Including Para Military Forces (Persons Holding Civil Posts Are Not Included).

Parents either or both of whom is or are in the rank of Colonel and above in the Army and to equivalent posts in the Navy and the Air Force and the para Military Forces; Provided that:-

- i) If the wife of an Armed Forces Officer is herself in the Armed Forces(i.e. the category under consideration) the rule of exclusion will apply only when she herself has reached the rank of Colonel;
- ii) The service ranks below Colonel or husband and wife shall not be clubbed together;
- iii) If the wife of an officer in the Armed Forces is in Civil employment, this will not be taken into account for applying the rule of exclusion unless she falls in the service category under item No. II in which case the criteria and conditions enumerated therein will apply to her independently.

IV Property Owners Agricultural Holdings.

Son(s) and daughter(s) of persons belonging to a family(father, mother and minor children) which owns land more than land permissible under the ceiling act of Haryana State.

V- Incom/Wealth Test.

Son(s) and daughter(s) of

- (a) Persons having gross annual income of Rs. 1.00 lac or above or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act for a period of three consecutive years. **(This ceiling has been enhanced from Rs. 1.00 lakh to Rs. 2.50 lakh vide Govt. letter No. 2077-SW(I)-2004 dated 30.9.2004).**
- (b) Persons in Categories I,II,III and IV who are not disentitled to the benefit of reservation but have income from other sources of wealth which will bring them within the income/wealth criteria mentioned in(a) above.

Explanation:

- i) Income from salaries or agricultural land shall not be clubbed;
- ii) The income criteria in terms of rupee will

be modified taking into account the change in its value every three years. If the situation, however, so demands, the interregnum may be less.

- iii) Where the husband is in some profession and the wife is in a class II or lower grade employment the income/wealth test will apply only on the basis of the husband's income.
- iv) If the wife is in any profession and the husband is in employment in a Class II or Lower rank post, then the income/wealth criteria will apply only on the basis of the wife's income and the husband's income will not be clubbed with it.

Explanation: Wherever, the expression 'Permanent incapacitation' occur in this schedule it shall mean incapacitation which results in putting an officer out of service.

क्रमांक 154-स0क0(1)-2002

प्रेषक

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार
अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
चण्डीगढ़ ।

सेवा में

- 1 सभी विभागाध्यक्ष हरियाणा राज्य में ।
- 2 आयुक्त अम्बाला, हिसार, रोहतक तथा गुड़गांवा मण्डल ।
- 3 सभी प्रबन्धक निदेशक, निगम/बोर्ड आदि हरियाणा राज्य में ।
- 4 रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट, चण्डीगढ़ ।
- 5 सभी उपायुक्त हरियाणा राज्य में ।
- 6 रजिस्ट्रार, सभी वि विद्यालय हरियाणा राज्य में ।

दिनांक : 06-02-2002

विशय: अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों से नौकरी हेतु आवेदन पत्र फीस तथा विभिन्न कोर्सों में दाखिले हेतु फीस/विवरण पत्रिका की निर्धारित राशि का 1/4 भाग लेने बारे ।

उपरोक्त विशय के सन्दर्भ में !

1. मुख्य सचिव, संयुक्त पंजाब सरकार के परिपत्र क्रमांक 6964-डबल्यू0जी0-53-62307 दिनांक 21-8-1953 के पैरा नं0 2-III के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के प्रारम्भ से की जाने वाली नियुक्तियों के समय अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित उम्मीदवारों से निर्धारित फीस का 1/4 भाग लिए जाने के निर्देश दिये गए थे। लेकिन सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि इन हिदायतों की दृढ़ता से पालना नहीं की जा रही है तथा अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों से निर्धारित फीस के 1/4 भाग से अधिक राशि वसूल की जा रही है ।
2. अतः इस मामले का निरीक्षण करने उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग/हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या अन्य किसी भी माध्यम से विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों से निर्धारित फीस तथा फार्म/प्रार्थना पत्र की कीमत का 1/4 भाग ही वसूल किया जाये । इसी प्रकार विभिन्न तकनीकी/व्यवसायिक/ शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए भी इन वर्गों के उम्मीदवारों से निर्धारित फीस/विवरण पत्रिका की राशि का 1/4 भाग ही लिया जाये
3. इन हिदायतों की दृढ़ता से पालना हेतु सभी सम्बन्धित के नोटिस में ला दिया जाये!

हस्ता/-
वि ेश सचिव
कृते: वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार
अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ।

पृ0क्रमांक 154-स0क0-1-2002

दिनांक 6-2-02

इसकी एक प्रति सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग व कर्मचारी चयन आयोग को भेजकर लिखा जाता है कि विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों से उक्त हिदायतों के अनुसार ही राशि वसूल की जाये ।

हस्ता/-
वि ेश सचिव
कृते: वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार
अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ।

पृ0क्रमांक 154-स0क0-1-2002

दिनांक 6-2-02

इसकी एक प्रति मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार सामान्य सेवाएं-III को उनके अ 110 क्रमांक 22/35/2001-3 जी0एस0 1 दिनांक 30-5-2001 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।

हस्ता/-
वि ेश सचिव
कृते: वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार
अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ।

**Relaxation of 5 years in upper age limit for sc and bc for entry into govt. Service.
No. 3/3/99-1 GS III**

From
The Chief Secretary to Government Haryana,
Chandigarh.

To

1. All Head of the Departments, Commissioners Ambala, Hisar, Gurgaon and Rohtak Divisions.
All Deputy Commissioners and All Sub-Divisional Officers(Civil) in Haryana State.
2. The Registrar, Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.

Dated Chandigarh, the 22nd Sept., 1999.

Subject:- Raising of age for entry into Government Service.

Sir,

I am directed to refer to Haryana Government letter No. 3/1/90-1 GS III, dated 5.9.90 on the subject noted above and to say that for the purpose of making recruitment to various services under the State Government, the general upper age limit prescribed at present under rule 3.6 of Punjab Civil Services Rules, Vol. I, Part-I is 35 years. The matter regarding raise in the upper age limit has been under consideration of Government for some time. In order to mitigate the hardship of educated unemployed youths, it has been decided that the existing general upper age limit for entry into service under the State Government shall, notwithstanding any provision to the contrary that may be contained in respective rules, be raised to 40 years subject to the following conditions:-

- (a) **The existing instructions in regard to the relaxation of 5 years in the upper age limit in respect of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes for appointment to gazetted as well as non-gazetted services or posts will continue to be in force.**
- (b) The relaxation in upper age limit for recruitment in respect of ex-servicemen as contained in Haryana Government Circular letter No. 4710-5GS-70/18998, dated the 15th July, 1970, will continue as heretofore. In other words, the candidates of this category may be recruited upto the age of 40 years plus continuous military service added by three years, and
- (c) If in certain service rules, the upper age limit higher than 40 years is permissible on account of special grounds or in certain circumstances those provisions shall continue to remain in force.

2. It is requested that these instructions may be noted carefully for immediate compliance and amendment in the relevant service rules, wherever considered necessary, should also be made in accordance with the circumstances/conditions pertaining in each service under your control.

3. The receipt of this letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,
Sd/-
Joint Secretary General Admn.,
For Chief Secretary to Govt. Haryana.

A copy is forwarded for similar action to all Financial Commissioner/Commissioners and Secretaries to Govt. Haryana for information and necessary action.

Sd/-
Joint Secretary General Admn.,
For Chief Secretary to Govt. Haryana.

To
All Financial Commissioner/Commissioners and Administrative Secretaries to Govt. Haryana.

U.O.No. 3/3/99-1GS-III Dated Chandigarh, the 22nd Sept. 1999

- 1 A copy is forwarded to the Financial Commissioner and Secretary to Govt. Haryana, Finance Department.
- 2 It is requested that the necessary steps may be taken to amend the Rule 3.6 of Punjab Civil Service Rules Vol. I Part-I in accordance with the above decision.

Sd/-
Joint Secretary General Admn.,
For Chief Secretary to Govt.

Haryana.To

Financial Commissioner and Secretary to Govt. Haryana, Finance Department.

U.O.No. 3/3/99-1GS-III Dated Chandigarh, the 22nd Sept. 1999

From
The Director General of Police,
Haryana.

To

The Director,
Welfare of Scheduled Castes & Backward Classes Department Haryana
Chandigarh.

No. 20511/E (II)-2 Dated Panchkula, the 28.09.2001

Subject: - Welfare programme for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes & Backward Classes.

Memo

Kindly refer to your letter No EC-223/2001/18723 dated 09.08.2001, on the above subject.

Relaxation to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes & Backward Classes being given at the time of Direct requirement are as under:-

- 1. Age relaxation:**-No person of General Category shall be appointed to the post of constable by Direct Recruitment who is less than 18 year or more than 27 years of at the time of enrolment. But the male/female candidates belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes & Backward Classes categories, relaxation of upper age limit of five years is given.
- 2. Physical standard relaxation:** - The candidate of general categories for recruitment as constable shall have minimum height of 5'-7" and normal chest measurement of 33" with expansion of 1-1/2". But for the candidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes categories relaxation in physical standard 1" in height and 1" in chest measurement is being given. For female candidate: - The female candidate of general category for recruitment as a constable shall have a minimum height of 5'-2" inch. However, the candidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes & Backward Classes categories, relaxation in physical standard to the extent of 1" in height is being given.
- 3. Educational qualification:** - The minimum educational qualification for a candidate of general category for selection as a constable is matriculation. However, for the male/female candidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes categories, the minimum educational qualification is 8th class pass.

The vacancies of SCs/STs and BC categories in ESM quota are filled up by the candidates of concerned ESM only, as per reservation policy.

Sd/-
(K.K.Mishra)
AIG/Admn,
For Director General of Police, Haryana.

प्रेषक

निर्देशक मत्स्य पालन हरियाणा,
पंचकूला ।

सेवा में

सभी जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
मत्स्य किसान विकास एजेंन्सी हरियाणा राज्य ।

यादी क्रमांक इन्वेस्टीगेटर-2006 / 9595-616
पंचकूला, दिनांक 19-5-2006

विशय:-

**Formulation of Special Component Plan for the year
2006-07.**

हरियाणा सरकार की हिदायतोंनुसार यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में सभी तालाबों में 20 प्रतिशत कोटा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित किया जाये ।

अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि जिन गांवों में 3 तालाब स्थित हैं, उनमें से एक तालाब जो मत्स्य पालन हेतु योग्य हो तथा जिसका क्षेत्रफल एक एकड़ से कम न हो वह तालाब अनुसूचित जाति परिवारों के लिए रिजर्व करते हुए निदेशक मत्स्य पालन को सूचना भेजें ! इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करें कि जिन गांवों के तालाबों को अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए आरक्षित किया गया है उन तालाबों को अनुसूचित जाति के परिवारों को ही पट्टे पर दिलवाया जाए ।

हस्त:

निर्देशक मत्स्य पालन, हरियाणा
पंचकूला !

CC: Director Social Welfare & Backward Classes Haryana
Director Rural Development Haryana.